राष्ट्रीय संगोष्ठी

"MAKE IN INDIA (THE REVOLUTIONARY PROJECT): PROSPECT & CHALLENGES"

"मेक इन इण्डिया (एक क्रान्तिकारी परियोजना): संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ"

03 एवं 04 मार्च 2016

**** प्रायोजक ****

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल

**** आयोजक ****

वाणिज्य विभाग
भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू
E.Mail- govt_mhowcollege03@rediffmail.com
दूरभाष 07324–226037

डॉ. कुसुमलता निगवाल
प्राचार्य/संरक्षक
भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू
मोबाईल 94259–48499

डॉ. आर.के. विपट
संयोजक
राष्ट्रीय संगोष्ठी
मोबाईल 94253–67979

डॉ. राजेश वर्मा
सचिव
राष्ट्रीय संगोष्ठी
मोबाईल 98263–20557

राष्ट्रीय संगोष्ठी

"MAKE IN INDIA (THE REVOLUTIONARY PROJECT): PROSPECT & CHALLENGES"

"मेक इन इण्डिया (एक क्रान्तिकारी परियोजना): संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ"

आमंत्रण–पत्र

पति,

श्रीमान्/श्रीमती/डॉ. .....

.....

.....

*** सलाहकार समिति ***

1. डॉ. जुलियट ओंकार – वरिष्ठ प्राध्यापक कला संकाय
2. डॉ. शोभा जैन – संकायाध्यक्ष कला
3. डॉ. रेखा किल्लेदार – संकायाध्यक्ष विज्ञान
4. डॉ. रशीदा कांचवाला – विभागाध्यक्ष गृहविज्ञान

*** वाणिज्य विभाग आयोजन समिति ***

1. डॉ. पी.के. सन्से – 9425315152
2. डॉ. संजय जौहरी – 9826093451
3. डॉ. दिलीप जैन – 9425347340
4. डॉ. जे.के. जैन – 9425791841
5. डॉ. जे.एस. मण्डलोई – 9893251867
6. डॉ. कृष्णा भूरिया – 9827375689

राष्ट्रीय संगोष्ठी

"MAKE IN INDIA (THE REVOLUTIONARY PROJECT): PROSPECT & CHALLENGES"

"मेक इन इण्डिया (एक क्रान्तिकारी परियोजना): संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ"

आयोजन 03 एवं 04 मार्च 2016

प्रतिभागी विवरण

1. नाम .....
2. पद .....
3. संस्था .....
   .....
4. शोध पत्र का शीर्षक .....
   .....
   .....
5. दूरभाष .....
6. ई.मेल. आय.डी. .....
7. श्रेणी : संकाय सदस्य/कार्पोरेट/शोधार्थी/विद्यार्थी

दिनांक ..... हस्ताक्षर

पंजीयन शुल्क

संकाय सदस्य	कार्पोरेट	शोधार्थी/विद्यार्थी
1000 रूपये	1200 रूपये	600 रूपये

टिप्पणी:—पंजीयन शुल्क का भुगतान प्राचार्य भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू के नाम से देय **डिमाण्ड ड्राफ्ट** या नगद जमा कराना होगा। पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। आवास व्यवस्था अतिरिक्त शुल्क एवं पूर्व सूचना पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रतिभागियों को किसी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। शोध पत्र के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में सभी का पंजीयन अनिवार्य है। (संगोष्ठी में प्राप्त शोधपत्रों को सम्पादित कर ISSN पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। शोध पत्र एवं सारांश भेजने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2016 है।)

शोध पत्र संबंधी जानकारी

शोध पत्र एवं शोध सारांश एम.एस. वर्ड में अंग्रेजी में टाईम्स न्यू रोमन फोन्ट साईज 12 एवं हिन्दी में कृतिदेव 010 फोंट साईज 14 तथा लाईन स्पेसिंग 1.5 होना चाहिए। शोधपत्र का आकार ए4 साईज का होना चाहिए। शोध सारांश अधिकतम 250 शब्द एवं शोध पत्र अधिकतम 2000 शब्दों का होना चाहिए। जिसमें लेखक एवं कीवर्ड का उल्लेख होना चाहिए। शब्द सीमा शीर्षक, नाम, ईमेल आदि छोड़कर मान्य होगी।

शोध पत्र की साफ्ट कॉपी निम्न ईमेल पर ही मान्य होगी :–

E-mail ID. nationalseminarmhowcollege@gmail.com

राष्ट्रीय संगोष्ठी

"MAKE IN INDIA (THE REVOLUTIONARY PROJECT): PROSPECT & CHALLENGES"

''मेक इन इण्डिया (एक क्रान्तिकारी परियोजना): संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ''

परिचय-

वर्तमान समय में भारत सरकार के नवीन आर्थिक विकास का मॉडल मूलतः भारत में निर्मित उत्पादों के निर्यात पर आधारित है। यह मॉडल घरेलू उद्यमियों को निर्यात के लिए उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित तो करता ही है, साथ ही विश्व की शीर्ष कम्पनियों को भी भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है। यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर है, जो कि क्रमशः विकसित होकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 60% है। दूसरी ओर, औद्योगिक क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी विगत 30वर्षो से 26% के लगभग है। इसमें भी विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) और भी कम होकर समग्र GDP का मात्र 14.9% है।

विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जो वर्तमान में Democracy, Demograpy और Demand के अद्वितीय संयोजन को प्रदर्शित करता है। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि भारत में सामान्य नागरिक की क्रय–क्षमता को बढ़ाया जाये, जिससे माँग और विकास को प्रोत्साहन मिले और साथ ही निवेशकों को भी आकर्षक प्रतिसाद मिल सके। भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास से यह लाभ होगा कि लोग गरीबी रेखा से शीघ्रता से ऊपर उठ सकेंगे और उन्हें मध्यम आय वर्ग में लाया जा सकेगा। इस परियोजना से वैश्विक व्यापार मे भी अवसरों की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि ''अधिक रोजगार अर्थात् अधिक क्रय शक्ति''। ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम का मूल लक्ष्य इसी भावना पर केन्द्रित है।

मेक इन इंडिया परियोजना भारत की नवीन सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि वे भारत में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न कर सकें। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (Foreign Direct Investment) को प्रथमतः भारत के विकास (First Develop India) के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत सरकार का प्रयास है कि निवेशक भारत को केवल एक बाजार ही नहीं अपितु एक अवसर के रूप में भी देखें, जहाँ न्यूनतम लागत में विनिर्माण किया जा सके और उपभोक्ता वर्ग भी उपलब्ध हो, क्योंकि ये दोनों ही भारत के आर्थिक चक्र को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मेक इन इंडिया को एक वृहद् दर्शन की तरह देखा जा रहा है जो व्यवसाय एवं व्यवसाय करने को आसान बनाएगा । यह प्रोजेक्ट "Look East –Link West" वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ''स्वच्छ भारत अभियान'' एवं "Waste to wealth" जैसे क्रान्तिकारी मॉडल पर भी जोर देता है, जो भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पब्लिक –प्राईवेट पार्टनरशिप के द्वारा भारत के लगभग 500 कस्बों में "Waste Water Management" एवं "Solid Waste Management" अभियान चलाये जा रहे हैं। भविष्य में ''स्मार्ट सिटी'' योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय अधोसंरचना तैयार की जा रही है, जिसमें हाइवे के साथ आइवे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गैस–ग्रिड एवं वाटर–ग्रिड जैसी महती योजनाएँ शामिल है।

इस प्रकार 'मेक इन इंडिया' परियोजना एक ऐसी संयुक्त समग्र योजना है, जो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि विशेषकर भारत के Manufacturing सेक्टर के विकास एवं पुनर्निर्माण पर केन्द्रित है। यह परियोजना विनिर्माण के लिए प्रशिक्षित मानवीय संसाधन भी उपलब्ध करावेगी।

उच्च शिक्षा के माध्यम से **मेक इन इंडिया** परियोजना को अधिक ऊँचाइयों पर ले जाया जा सकता है। यदि महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र के यथार्थ वातावरण में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी प्रशिक्षण दिया जाये, तो उनके कार्य करने की क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि सम्भव है। इसके लिए महाविद्यालयीन परिसरों में शिक्षा एवं वांछित औद्योगिक ज्ञान में समन्वय बनाना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालयीन शिक्षा पाठ्यक्रमों में 'कौशल– विकास' को सम्मिलित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

यद्यपि इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं, किन्तु प्रस्तावित सेमिनार सभी बुद्धिजीवियों एवं शोधार्थियों को एक अवसर प्रदान करेगा कि वे इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के चक्र में आने वाली समस्याओं के प्रभावी निराकरण एवं सुझावों द्वारा अपने विचारों का आदान–प्रदान कर सके। यह एक ऐसी समग्र परियोजना है जो भारत को आर्थिक रूप सें सुदृढ़ बनाने के साथ ही साथ विश्व स्तर पर भू–राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित कर सकेगी।

उपर्युक्त संदर्भ में वाणिज्य संकाय, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू समस्त शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों, एवं कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार एजेंसी के अधिकारियों को मौलिक विचारों एवं शोधपत्रों की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता है।

PROGRAMME – SCHEDULE

[3 मार्च 2016, गुरूवार]

प्रातः	09:30 – 10:30	-	पंजीयन एवं स्वल्पाहार
प्रातः	10:30 - 12:00	-	उद्घाटन सत्र
दोपहर	12:00 – 12:15	-	चाय
दोपहर	12:15 – 02:15	-	द्वितीय सत्र (तकनीकी)
दोपहर	02:15 – 03:00	-	भोजन
दोपहर	03:00 – 05:00	-	तृतीय सत्र (तकनीकी)

[4 मार्च 2016, शुक्रवार]

प्रातः	09:30 – 10:30	-	स्वल्पाहार
प्रातः	10:30 - 12:00	-	चतुर्थ सत्र (तकनीकी)
दोपहर	12:00 – 12:15	-	चाय
दोपहर	12:15 – 2:15	-	पंचम् सत्र (तकनीकी)
दोपहर	02:15 – 3:00	-	भोजन
दोपहर	03:00 – 5:00	-	षष्ठम् समापन समारोह

कार्यक्रम एवं विषयवस्तु

[गुरूवार, दिनांक 3 मार्च, 2016]

सत्र–प्रथम :–उद्घाटन एवं प्रमुख वक्तव्य (Key-note Speech)

सत्र– द्वितीय:

मेक इन इंडिया एवं भारतीय मूल्य

1. विनिर्माण एवं भारतीय मूल्य
2. थोक एवं खुदरा बिक्री तथा भारतीय मूल्य
3. विपणन एवं भारतीय मूल्य
4. विज्ञापन/वितरण एवं भारतीय मूल्य
5. सेवा प्रक्षेत्र एवं भारतीय मूल्य

सत्र –तृतीय:

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियारा (DMIC) एवं नवीन विनिर्माण नीति

- DMIC-संकेन्द्रित उद्योग: खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, औषधि निर्माण उद्योग, बायोटेक एवं सामान्य उत्पादन उद्योग
- भारत एक वैश्विक उत्पादन एवं विनियोग स्थल के रूप में, स्मार्ट शहर की अवधारणा, विनियोग क्षेत्र–पिथमपुर–धार–महू
- नवीन विनिर्माण नीति के प्रमुख तत्व

1. नीति प्रपत्र
2. कौशल विकास एवं तकनीकी विकास
3. अधोसंरचना का विकास
4. सुगम वित्त की उपलब्धता
5. व्यापार करने की सुगमता
6. नियामक वातावरण का सरलीकरण, निर्गमतंत्र, राष्ट्रीय विनियोग एवं विनिर्माण प्रक्षेत्र (NIMZ)
7. सम्पत्तियों का अधिग्रहण एवं हस्तान्तरण

[शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016]

सत्र–चतुर्थ:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR)

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रक्षेत्र में प्रतिबन्ध एवं **CAPS** के निषेध
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वचालित एवं शासकीय तरीके, लाभांश एवं पूँजी की पुनरावृत्ति, करारोपण के पहलू
4. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नवीन प्रेरणाएं/प्रोत्साहन
5. भारतीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार की ताकत, बौद्धिक सम्पदा (पेटेन्ट, डिजाईन, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क) सम्बन्धी भारतीय विधि (कानून) एवं प्रशासन
6. बौद्धिक सम्पदा प्रक्रियांकन, पारदर्शिता एवं प्रयोक्ता–मित्रता में उत्तम व्यवहार अपनाये जाने के सम्बन्ध में नई सरकार द्वारा की गई पहल।

सत्र–पंचम:

मेक इन इंडिया हेतु उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास

1. वर्तमान परिदृश्य।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी एवं संधारणीय विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका।
3. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में कौशल विकास की आवश्यकता, अवधारणा, सिद्धांत एवं व्यावहारिकता।
4. कार्यस्थल पर उच्च शिक्षा का पारगमन, मेक इन इंडिया परियोजना के विशेष सन्दर्भ में उच्च शिक्षा व उद्योग का अनुबंधन।

सत्र– षष्ठम् :–समापन समारोह